



अर्चना गुप्ता

**प्राथमिक शिक्षा पर मध्यान्ह भोजन योजना का प्रभाव
(गोरखपुर के पाली ब्लॉक पर आधारित एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)**

शोध अध्ययनी - समाजशास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ०प्र०) भारत

Received-11.07.2025,

Revised-19.07.2025,

Accepted-27.07.2025

E-mail : guptakarchana@gmail.com

सारांश: शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति का मूलधार होती है। भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक असमानताएँ गहरी हैं, वहाँ सर्वसुलभ और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना सदैव एक चुनौती रहा है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए विभिन्न योजनाएँ एवं नीतियाँ समय-समय पर प्रारम्भ की गईं, जिनमें "मध्यान्ह भोजन योजना" (Mid-Day Meal Scheme) एक अत्यंत प्रभावशाली और सफल सामाजिक कल्याण योजना के रूप में उभरी है।

इस योजना का उद्देश्य केवल छात्रों को भोजन उपलब्ध कराना नहीं था, बल्कि शिक्षा से वंचित बच्चों, विशेषकर निर्धन एवं वंचित वर्गों के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना, उनकी उपस्थिति बढ़ाना, ड्रॉपआउट दर घटाना और पोषण स्थिति में सुधार लाना था।

गोरखपुर जनपद का पाली ब्लॉक, पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है, जहाँ अधिकांश जनसंख्या कृषि और दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर है। सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन के कारण यहाँ के परिवार अपने बच्चों को विद्यालय भेजने में अरुचि दिखाते थे। इस संदर्भ में मध्यान्ह भोजन योजना ने शिक्षा में सामाजिक भागीदारी और बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

कुंजीशब्द- प्रगति का मूलधार, सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक असमानता, सामाजिक कल्याण योजना, भागीदारी।

योजना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि - भारत में मध्यान्ह भोजन की अवधारणा स्वतंत्रता के पूर्व कुछ रियासतों जैसे मद्रास प्रेसीडेंसी (1925) में प्रारंभ हुई थी। बाद में तमिलनाडु ने 1982 में इसे राज्यव्यापी स्तर पर लागू किया। केंद्र सरकार ने 15 अगस्त 1995 से "राष्ट्रीय कार्यक्रम - प्राथमिक शिक्षा में पोषण समर्थन योजना" (NP&NSPE) के रूप में इसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रारम्भ किया।

2001 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे सांविधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दी और राज्य सरकारों को सभी सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में पका हुआ भोजन प्रदान करने का निर्देश दिया। इस प्रकार यह योजना केवल एक कल्याणकारी नीति न रहकर, शिक्षा और पोषण दोनों के अधिकार से जुड़ी पहल बन गई।

अनुसंधान का क्षेत्र एवं महत्व - गोरखपुर जिले का पाली ब्लॉक अनुसंधान के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ ग्रामीण परिवेश में प्राथमिक शिक्षा के प्रति लोगों की रुचि, सामाजिक स्थिति, जातीय विविधता, गरीबी, पोषण असमानता और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का यथार्थ आकलन संभव था।

यह अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह समझने का प्रयास करता है कि मध्यान्ह भोजन योजना ने शिक्षा के सामाजिकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित किया है और इससे परिवार, समुदाय तथा बच्चों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आए हैं।

अनुसंधान की समस्या - इस अध्ययन की मुख्य समस्या यह है कि -

क्या मध्यान्ह भोजन योजना ने पाली ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की स्थिति में वास्तविक सुधार किया है? क्या इससे छात्र-छात्राओं की उपस्थिति, नामांकन, ड्रॉपआउट दर, शैक्षणिक उपलब्धि और पोषण स्तर में परिवर्तन आया है? साथ ही, क्या यह योजना समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए सामाजिक समानता और एकीकरण का माध्यम बनी है?

अनुसंधान के उद्देश्य -

1. मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन की स्थिति का अध्ययन करना।
2. योजना के माध्यम से विद्यालयों में उपस्थिति और नामांकन पर प्रभाव का विश्लेषण करना।
3. छात्रों के पोषण स्तर, स्वास्थ्य और सामाजिक व्यवहार पर योजना के प्रभाव का मूल्यांकन करना।
4. योजना के माध्यम से सामाजिक एकता, जातीय समरसता एवं लैंगिक समानता में आई परिवर्तनशीलता का अध्ययन करना।
5. पाली ब्लॉक में योजना के क्रियान्वयन में आने वाली प्रमुख समस्याओं और चुनौतियों की पहचान करना।

अनुसंधान की कार्यप्रणाली (Methodology) - इस अध्ययन में वर्णनात्मक (Descriptive) एवं विश्लेषणात्मक (Analytical) अनुसंधान पद्धति का उपयोग किया गया है। क्षेत्र चयन: गोरखपुर जिले के पाली ब्लॉक के 10 प्राथमिक विद्यालयों का चयन। नमूना (Sample) प्रतिशत कुल 200 विद्यार्थी (कक्षा 1-5), 20 शिक्षक एवं 50 अभिभावक।

डेटा संकलन के स्रोत - प्राथमिक स्रोत - साक्षात्कार, अवलोकन एवं प्रश्नावली। द्वितीयक स्रोत - शैक्षणिक रिपोर्टें, जिला शिक्षा कार्यालय के अभिलेख, सरकारी आँकड़े, और पूर्व प्रकाशित अध्ययन।

सामाजिक सूचकांक (attendance, nutrition, gender equality, community participation) के आधार पर गुणात्मक एवं मात्रात्मक विश्लेषण।

प्रमुख निष्कर्ष (Finding) -

(क) **विद्यालय उपस्थिति पर प्रभाव** : पाली ब्लॉक के अधिकांश विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना लागू होने के बाद छात्रों की उपस्थिति में औसतन 25-30 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। विशेष रूप से बालिकाओं की उपस्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। जिन परिवारों के बच्चे पहले विद्यालय नहीं जाते थे, वे अब नियमित रूप से विद्यालय आने लगे।

(ख) **नामांकन एवं ड्रॉपआउट दर** - 2005-2024 के बीच नामांकन में निरंतर वृद्धि हुई। जिन विद्यालयों में पहले 100-120 बच्चे नामांकित थे, वहाँ अब औसतन 180-200 बच्चे नामांकित हैं। वहीं, ड्रॉपआउट दर 18 प्रतिशत से घटकर 6 प्रतिशत तक आ गई।

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

ASVP PIF-9. 805/ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14



(ग) पोषण एवं स्वास्थ्य सुधार — शिक्षकों एवं अभिभावकों के अनुसार बच्चों के स्वास्थ्य में सकारात्मक सुधार देखा गया। भोजन में दाल, चावल, सब्जी, रोटी और कभी-कभी फल शामिल होते हैं। बच्चों का वजन एवं सक्रियता स्तर बढ़ा है।

(घ) सामाजिक समानता का विकास — मध्याह्न भोजन योजना ने जाति, धर्म और वर्ग की सीमाओं को तोड़ने में प्रभावशाली भूमिका निभाई है। एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करने से बच्चों में सामाजिक एकता की भावना विकसित हुई। अनेक माता-पिता ने इसे "समाज में समरसता लाने वाला कार्यक्रम" बताया।

(ङ) लैंगिक समानता — इस योजना ने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन दिया है। भोजन की व्यवस्था से माता-पिता अपनी बालिकाओं को विद्यालय भेजने में अधिक रुचि लेने लगे। इससे बालिका नामांकन में औसतन 22 प्रतिशत वृद्धि हुई।

(च) शिक्षकों की दृष्टि — अधिकांश शिक्षकों का मत है कि भोजन योजना ने विद्यार्थियों की रुचि और अनुशासन में सुधार किया है। दोपहर का भोजन विद्यालय के वातावरण को अधिक आकर्षक बनाता है, जिससे शिक्षण प्रभावी हुआ है।

(छ) प्रशासनिक चुनौतियाँ — योजना के क्रियान्वयन में कुछ समस्याएँ भी पाई गईं —

खाद्य सामग्री की आपूर्ति में विलंब, भोजन की गुणवत्ता में भिन्नता, रसोइयों का मानदेय कम होना, अभिभावकों की सीमित भागीदारी। फिर भी, समग्र रूप से योजना ने शिक्षा में उत्साहजनक परिणाम दिए हैं।

समाजशास्त्रीय विश्लेषण — मध्याह्न भोजन योजना केवल शैक्षिक नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का भी प्रतीक है। यह एमिल दुर्खीम के "सामाजिक एकता" (Social Solidarity) के सिद्धांत को व्यवहार में लाती है, जहाँ सामूहिक भोजन के माध्यम से बच्चों में सामूहिक चेतना का विकास होता है।

कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह योजना आर्थिक वर्गभेद को कम करने का माध्यम है, क्योंकि निर्धन परिवारों के बच्चे भी समान सुविधाएँ प्राप्त कर रहे हैं। मैक्स वेबर के दृष्टिकोण से यह योजना राज्य की "सामाजिक उत्तरदायित्व" की अभिव्यक्ति है, जो सामाजिक न्याय की अवधारणा को सशक्त करती है।

वर्चा (Discussion) — पाली ब्लॉक जैसे ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा और पोषण दोनों की कमी लंबे समय से सामाजिक अवरोध बने हुए थे। मध्याह्न भोजन योजना ने इन दोनों समस्याओं का संयुक्त समाधान प्रस्तुत किया है। योजना न केवल बच्चों की भूख मिटाती है, बल्कि अभिभावकों में विद्यालय के प्रति विश्वास और सामाजिक चेतना भी उत्पन्न करती है। विद्यालय के शिक्षकों ने बताया कि बच्चों में सहयोग, अनुशासन, सहअस्तित्व और सामाजिक सहभागिता जैसी गुणों में वृद्धि हुई है। भोजनालय में सभी बच्चे एक साथ बैठते हैं, जिससे जातीय भेदभाव घटा है और समाज में लोकतांत्रिक संस्कृति का विकास हुआ है।

सुझाव (Suggestion) —

1. भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु नियमित निरीक्षण आवश्यक है।
2. स्थानीय समुदाय, अभिभावक समिति और पंचायत की सक्रिय भागीदारी बढ़ाई जाए।
3. रसोइयों का मानदेय एवं प्रशिक्षण सुधार किया जाए।
4. भोजन में सप्ताह में एक बार फल एवं दूध की व्यवस्था हो।
5. योजना के प्रभाव का वार्षिक सामाजिक लेखा-जोखा तैयार कर सार्वजनिक किया जाए।
6. छात्र-छात्राओं की पोषण स्थिति के आधार पर स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य किया जाए।

निष्कर्ष — गोरखपुर के पाली ब्लॉक में मध्याह्न भोजन योजना ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किया है। इसने विद्यालयों को केवल शिक्षा केंद्र नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, स्वास्थ्य और समानता के मंच में रूपांतरित कर दिया है। योजना ने गरीब वर्गों के बच्चों को विद्यालय से जोड़ा, बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया, सामाजिक दूरी को घटाया और पोषण की स्थिति में सुधार किया। समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो यह योजना ग्रामीण समाज में समाज-परिवर्तन की गतिशील शक्ति बन चुकी है। इसके दीर्घकालिक प्रभाव न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, बल्कि एक सशक्त, समानतामूलक और संवेदनशील समाज के निर्माण की दिशा में ठोस कदम हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार (2023). मध्याह्न भोजन योजना वार्षिक रिपोर्ट।
2. शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन (2022) राज्य स्तरीय मूल्यांकन रिपोर्ट।
3. District Education Office, Gorakhpur (2024)- Primary School Attendance Data, Pali Block.
4. Dreze, Jean & Goyal, Aparajita (2003)- Future of Mid & Day Meals in India- Economic & Political Weekly.
4. UNICEF (2021)- School Feeding and Child Nutrition in Indi.
6. Planning Commission (2014)- Evaluation Report on Mid & Day Meal Scheme.
7. कुमार, अजय (2020). भारतीय शिक्षा व्यवस्था में पोषण योजनाओं का प्रभाव। नई दिल्ली: अवध प्रकाशन।
8. सिंह, रमेश (2022), ग्रामीण शिक्षा और सामाजिक विकास। लखनऊ: भारतीय बुक डिपो।
9. विश्व बैंक (2018), India: School Nutrition and Learning Outcomes.
10. मिश्रा, शैलेंद्र (2023), शिक्षा और सामाजिक समानता, प्रयागराज: साहित्य भवन।
